इकाई- 1

1

अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास

भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है । इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी हैं । 15 अगस्त, 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था । उस समय भारत को "सोने की चिड़ियाँ" कहा जाता था । लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़ियाँ का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही ।

आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरूत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी।

इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएँ एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है।

अर्थव्यवस्था का परिचय

अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश (Colony) बनाकर रखा था । उन्होंने **"फूट डालो और शासन करो"** (Divide and Rule) की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा । ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गयी । गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था । अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ । प्रति व्यक्ति

आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया ।

उपनिवेश (Colony)

जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है । भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था ।

अर्थव्यवस्था का अर्थ

हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय: सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं । इनकी क्रियाएँ मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है । उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल-कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट-कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने-अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं ?

इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी हो सके। **हमारी वे सभी क्रियाएँ, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है ।**

अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढाँचा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ सम्पादित की जाती है, जैसे-कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि । ये आर्थिक क्रियाएँ एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ एवं सेवाओं का संपादन करती है तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके ।

इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है-

(i) लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का **उत्पादन** करती है ।

(ii) लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है;

आर्थर लेविस (Arthur Lewis) के अनुसार "**अर्थव्यवस्था का अर्थ**" **किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है ।**"

ब्राउन (Brown) के अनुसार "**अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है।**" (Economy is the system of earning livelihood.)

दूसरे शब्दों में, "**अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अन्तर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं ।**"

संक्षेप में, "**अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है ।**"

इसी प्रकार **बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ** बिहारवासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसके आधार पर बिहारवासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है ।

अर्थव्यवस्था की संरचना या ढाँचा (Structure of Economy)

अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूँकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ अथवा गतिविधियाँ सम्पादित की जाती हैं, जैसे- कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि । इन क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बाँटा जाता है -

(i) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

(ii) द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

(iii) तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector or Service Sector)

ABDIEL SOLUTIONS ABSOL * PATNA *

सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी तीन भागों में बाँटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना

(Structure of the Indian Economy)

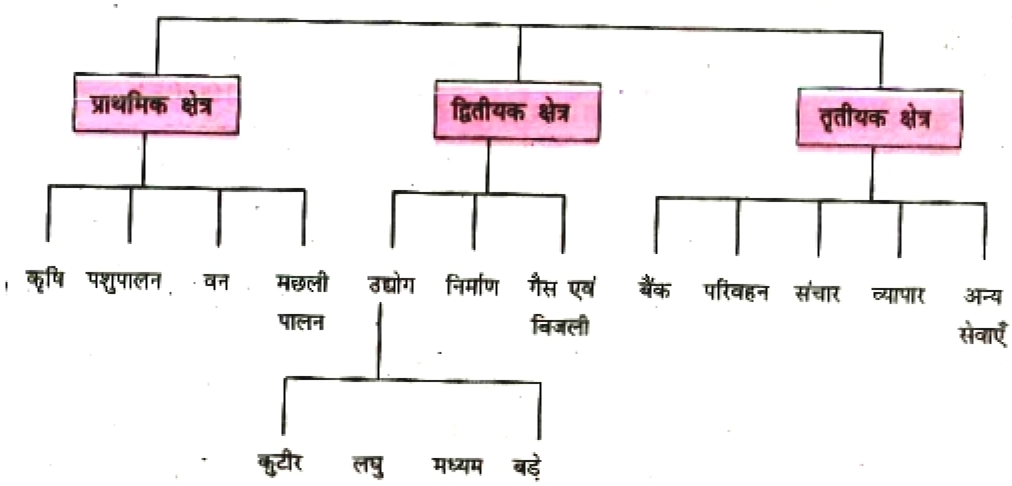

(i) प्राथमिक क्षेत्र- प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं।

(ii) द्वितीयक क्षेत्र- द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएँ, जैसे- गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं।

(iii) तृतीयक क्षेत्र- तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएँ प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है।

राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों के योगदान को एक तालिका के द्वारा समझा जा सकता है-

तालिका 1.1 राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

क्षेत्र	वर्ष 1901 में	वर्ष 1947 में	वर्ष 2007 में
1. प्राथमिक क्षेत्र	63.6	58.7	22.0
2. द्वितीयक क्षेत्र	12.7	14.3	22.0
3. तृतीयक क्षेत्र	23.7	27.0	56.0
	100.0	100.0	100.0

तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7 प्रतिशत था जो घटकर अब केवल 22 प्रतिशत रह गया है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3 प्रतिशत था अब वह बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27.0 था जो बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।

अर्थव्यवस्था के प्रकार (Types of Economy)

आज विश्व में निम्न तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है -

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)– पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे- अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि।

2. समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)– समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्युबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है।

ABDIEL SOLUTIONS ABSOL PATNA

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)– मिश्रित अर्थव्यवस्था पूँजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन

के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है । भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है । यह अर्थव्यवस्था पूँजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है । (It is a mid way between capitalism and socialism.)

अर्थव्यवस्था का विकास

अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है । अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है । जिस तरह एक पौधे का क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानवहित में होता है । ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है । अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं ।

अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा । **भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है । इसका एक अपना इतिहास है ।**

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों का विवेचन करेंगे जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएँ हैं-

(i) आर्थिक विकास तथा (ii) मौद्रिक विकास ।

(i) आर्थिक विकास- पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन (Economic Planning) के द्वारा सम्पन्न होता है । इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या ?

ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है । इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है । फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लें । **प्रो० रोस्टोव** (Rostow) के अनुसार, ''आर्थिक विकास एक ओर श्रम-शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का सम्बन्ध है ।''

SOLUTIONS ABSOL PATNA

समावेशी विकास (Inclusive Growth)

आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन-स्तर ऊँचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास (Inclusive Growth) कहा जाता है ।

प्रो0 मेयर एवं बाल्डविन (Meier and Baldwin) ने बताया है कि "आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ।" (Economic Development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time.)

अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढाँचे में परिवर्तन होते हैं । इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं । **आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊँचा स्तर प्राप्त करना होता है ।** इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है ।

आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान लें कि **आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है ?**

सामान्यतः आर्थिक विकास (Economic Development) तथा आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) में कोई अंतर नहीं माना जाता है । दोनों शब्दों को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है । लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अन्तर किया जाने लगा है ।

SOLUTIONS ABSOL PATNA

श्रीमती उर्सला हिक्स (Mrs. Urshala Hicks) के अनुसार, "वृद्धि (Growth) शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है जबकि विकास (Development) शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है ।" **डॉ० ब्राईट सिंह** (Dr. Bright Singh) ने भी लिखा है कि Growth शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है ।"

सतत् विकास (Sustainable Development)

आज प्राकृतिक साधनों जैसे- कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण (Environment Pollution) की गंभीर समस्या को जन्म दिया है । अनेक उत्पादन क्रियाएँ जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है जो आज एक चिंता का विषय है । इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। **इसके विकल्प के रूप में सतत् विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है ।**

सतत् विकास का शाब्दिक अर्थ है- **ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत् विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है ।**

ब्रुण्डलैंड आयोग (Brundland Commission) ने सतत् विकास के बारे में बताया है कि **"विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएँ, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं से समझौता किए, पूरी की जाती है ।"**

इसी तरह **मैड्डीसन** (Maddison) नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि **धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर 'आर्थिक वृद्धि' (Economic Growth) का सूचक होता है जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर "आर्थिक विकास" (Economic Development) का सूचक होता है।**

जहाँ तक आर्थिक प्रगति (Economic Progress) की बात है, यह एक व्यापक शब्द है । इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं । **प्रायः "आर्थिक प्रगति" के स्थान पर "आर्थिक वृद्धि" या "आर्थिक विकास" शब्दों का प्रयोग होता है ।** आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक-दूसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं । सच पूछा जाए तो "विकास" शब्द में "वृद्धि" शब्द का अर्थ भी निहित है । अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक

प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है । इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है । **प्रो० लेविस** (Prof. Lewis) की भी यही राय है।

अब आप **आर्थिक नियोजन** (Economic Planning) के बारे में जान सकते हैं जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है ।

आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयवद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है ।

भारत में एक **योजना आयोग** (Planning Commission) है जो आनेवाले पाँच वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है । **भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950 को किया गया** । इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं । योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह हैं ।

योजना आयोग के शब्दों में- ''आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है''। अर्थात् "Economic Planning means utilisation of country's resources into different development activities in accordance with national priorities."

भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है तथा अब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है । भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951-1956 थी तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007-2012 है। **भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है ।** भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है- आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का

> **आर्थिक नियोजन का अर्थ**
> **राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है ।**

भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था । आयोग के अध्यक्ष पदेन (Ex-officio) भारत के प्रधानमंत्री होते हैं । सामान्यत: काम-काज एक उपाध्यक्ष की देख-रेख में होता है जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं।

आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय (Social justice) को बढ़ावा देना। भारत में नियोजन को एक तालिका 1.2 द्वारा आप समझ सकते हैं ।

तालिका 1.2 भारत में नियोजन

योजना	समय
पहली पंचवर्षीय योजना	1951-1956
दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956-1961
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-1990
दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002-2007
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007-2012

राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council- N.D.C.)

भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था । राष्ट्रीय विकास परिषद् में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन् सदस्य होते हैं । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अन्त में यह राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित (Approved) होती है ।

(ii) मौद्रिक विकास - वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख-सुविधाएँ उपलब्ध है । यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख-सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ा है । जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन-देन कर अपनी

आवश्यकता की पूर्ति करते थे । अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को **वस्तु-विनिमय प्रणाली** (Barter system) कहा जाता है । वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। चूँकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी । इसलिए वस्तुओं के लेन-देन (आदान-प्रदान) से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी ।

लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे-से कस्बे से बढ़कर बड़े गाँव एवं क्षेत्र में मनुष्यों का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई **मुद्रा (Money)** का **प्रादुर्भाव** हुआ । अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय (Exchange) की क्रिया होने लगी । अब दूर-दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि **मुद्रा एक सामान्य क्रय-विक्रय के साधन का कार्य** करने लगा । अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक **सरकार (Government) का अभ्युदय** हुआ । **सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा** ।

अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे ।

फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण (Transfer) किया जाने लगा जिसे हम चेक (Cheque) कहते हैं । इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है और **सरकारी आधिपत्य** से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान-प्रदान होता है।

आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है जिसे हम **कम्प्यूटर** (Computer) कहते हैं । यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण-शक्ति रखता है । बिजली से चलनेवाला यह मशीन, जिसे हम कम्प्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान-प्रदान में भी सहयोग देता है । कम्प्यूटर कैसा होता है ? इसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है । आजकल कम्प्यूटर सूचना शिक्षा एवं ज्ञान का सर्व सुलभ साधन हो गया है । प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहाँ बड़ा कम्प्यूटर लोगों के उपयोग में था वही अब

लैप टॉप काफी प्रचलन में है। मोबाइल में भी कम्प्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका है।

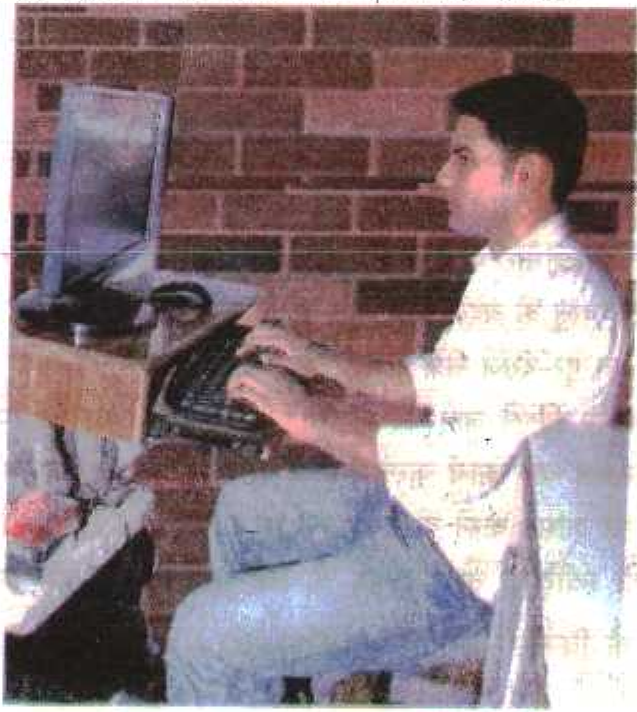

चित्र 1.1 कम्प्यूटर : एक नई खोज

आजकल प्लास्टिक (Plastic) के एक छोटे-से टुकड़े पर इंगित यांत्रिकी चिह्न के माध्यम से पैसे का आदान-प्रदान तथा निकासी होने लगा है । जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलम्ब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन-देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को **कोर बैंकिंग प्रणाली** (Core Banking System) कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति **प्लास्टिक** (Plastic) के यांत्रिकी संकेत (Mechanical Mark) से किसी भी समय बैंक के एक चिह्नित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है । ये सारी क्रियाएँ बिजली से संचालित कम्प्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिह्नित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम (ATM= Automatic Teller Machine) कहते हैं।

इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला-बदली के युग से हमलोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया है । आज हमलोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग

तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं । **एटीएम के अलावे हमें आज डेबिट कार्ड (Debit Card) तथा क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की भी सुविधा प्राप्त है ।** इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे ।

मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी

1. **वस्तु-विनिमय प्रणाली-** वस्तु से वस्तु का लेन-देन ।
2. **मौद्रिक प्रणाली-** मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय ।
3. **बैंकिंग प्रणाली-** बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का सम्पादन।
4. **कोर बैंकिंग प्रणाली** के अन्तर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण (Transfer)।
5. **एटीएम (ATM) प्रणाली-** प्लास्टिक के एक छोटे-से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केन्द्र से पैसे निकालने की सुविधा।
6. **डेबिट कार्ड** (Debit Card)- बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना ।
7. **क्रेडिट कार्ड** (Credit Card)- बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना ।

मुद्रा के इस विकास को एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है ।

ABDIEL SOLUTIONS PATNA ABSOL

सिंगासनी गाँव की कहानी

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अन्तर्गत सिंगासनी गाँव का एक लड़का छोटू प्राय: अपनी माँ को सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी-मोटी जरूरतों जैसे- चीनी, कागज, पेंसिल आदि की जरूरत होती तो उसकी माँ उसे गाँव के दूकानदार से उन छोटी-मोटी चीजों को लाने के लिए अनाज देती है । छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं । छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था । एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को

अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े-से दूकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दूकानदार को दिया जो कम्प्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया ।

अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले ?श्याम कुमार ने धीरे-से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं । तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर से सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है और आज हम जो प्लास्टिक (Plastic) के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं वह कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली है । आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं। अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को जिसे **Credit Card** अथवा **Debit Card** कहते हैं, से भी कर सकते हैं । छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने गाँव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया।

आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक

राष्ट्रीय आय (National Income)- राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है । किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है । सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है ।

प्रति व्यक्ति आय (Per capita Income)- आर्थिक विकास की माप करने के लिए

प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है । प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है । राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है । फार्मूले के रूप में-

$$\text{प्रतिव्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

विश्व बैंक (World Bank) की विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report), 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रतिव्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश (समृद्ध देश) है और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश (विकासशील) कहा गया है । भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रतिवर्ष थी ।

कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है । यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है -

तालिका 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

राज्य	2000-2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
पंजाब	26000
केरल	22800
बिहार	5700

ABDIEL SOLUTIONS ABSOL PATNA

तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन तीन राज्यों में पंजाब की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की प्रतिव्यक्ति आय सबसे कम है । अगर विकास को मापने के लिए प्रतिव्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा ।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा महबूब-उल-हक (Mahbub-Ul-Haq) के निर्देशन में तैयार की गई पहली **मानव विकास रिपोर्ट** (Human Development Report) में प्रस्तावित किया गया था । यूएनडीपी (UNDP) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट (HDR) विभिन्न

देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है । जहाँ तक **मानव विकास सूचकांक (HDI)** का प्रश्न है तो इसके तीन सूचक हैं - (i) जीवन आशा, (ii) शिक्षा प्राप्ति तथा (iii) जीवन-स्तर ।

फार्मूले के रूप में-

HDI = जीवन आशा सूचकांक + शिक्षा प्राप्ति सूचकांक + जीवन स्तर सूचकांक

HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की HDI दर शून्य से एक होती है ।

भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका 1.4 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

तालिका 1.4 2004 के लिए विभिन्न देशों के HDI मूल्य

देश	HDI मूल्य	HDI क्रम
नार्वे	0.965	1
ऑस्ट्रेलिया	0.957	3
श्रीलंका	0.755	93
पाकिस्तान	0.539	134
भारत	0.611	126
चीन	0.768	81
बंगलादेश	0.530	137

स्रोत - UNDP मानव विकास रिपोर्ट, 2006

चूँकि 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी। इसमें भारत का HDI मूल्य 0.611 है तथा 126 क्रम पर है । इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है । लिंग विकास सूचकांक (GDI) की दरों में भारत ने 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें क्रम पर आ गया था ।

यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा-सा देश श्रीलंका भारत से आगे है और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है । किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट(National Human Development Report)- UNDP की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल, 2002 में जारी की गई । योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 23 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में जारी किया । रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के० सी० पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है । इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (NHDR) में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न-भिन्न थी । केरल का रैंक सबसे ऊपर था जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश (BIMARU) का रैंक सबसे नीचे था ।

निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक (Human Poverty Index) निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात (Poverty Ratio) से काफी मिलता-जुलता है । राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक (HPI) में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है ।

उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत् कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुई है ।

आधारिक संरचना
(Infrastructure)

आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं । **वे सभी तत्त्व, जैसे- बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, उन्हें देश का आधारिक संरचना (आधारभूत ढाँचा) कहा जाता है।** किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढाँचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा।

बिहार के विकास की स्थिति

बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है । यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था । महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया था । चन्द्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरुगोबिन्द सिंह, बाबू वीर कुँवर सिंह, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था । बिहार में ही महात्मा गाँधी ने **''चम्पारण आंदोलन''** का बिगुल फुँका था । बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने **''संपूर्ण क्रांति''** का नारा दिया था । लोकगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था ।

लेकिन वहीं बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है । यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है । **साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है** । आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है ।

बिहार के पिछड़ेपन के कारण- आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है-

बिहार के पिछड़ेपन के कारण

1. तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या
2. आधारिक संरचना का अभाव
3. कृषि पर निर्भरता
4. बाढ़ तथा सूखा से क्षति
5. औद्योगिक पिछड़ापन
6. गरीबी
7. खराब विधि व्यवस्था
8. कुशल प्रशासन का अभाव

1. तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या- बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं । अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण-पोषण में चला जाता है ।

2. आधारिक संरचना का अभाव- किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है। लेकिन बिहार इस मामले में पीछे हैं । राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है । साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ भी कम है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है ।

3. कृषि पर निर्भरता- बिहार की

अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है । यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है । इसके चलते उपज कम होती है ।

4. बाढ़ तथा सूखा से क्षति– बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है । हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है । पिछले साल 2008 में कोशी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है । इससे कितने जान-माल की क्षति हुई । इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला । इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफी बर्बादी हुई । इसे चित्र सं॰-1.2 द्वारा समझाया गया है –

चित्र 1.2 बाढ़ की स्थिति

इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है । इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है । इसे चित्र सं॰ 1.3 द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है।

चित्र 1.3 सूखा की स्थिति

ABDUL SOLUTIONS ABSOL PATNA

इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है।

5. औद्योगिक पिछड़ापन- किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है। लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएँ सभी झारखण्ड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई है।

6. गरीबी- बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफी अधिक है। राज्य में प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है।

7. खराब विधि व्यवस्था- किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है। लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है।

8. कुशल प्रशासन का अभाव- बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं।

तालिका 1.5 बिहार की स्थिति

देश	बिहार	भारत
जनसंख्या 2001	8.29 करोड़	102.9 करोड़
जनसंख्या वृद्धि दर	2.5 प्रतिशत	1.9 प्रतिशत
साक्षरता दर कुल	47.53 प्रतिशत	65.4 प्रतिशत
साक्षरता पुरुष	60.3 प्रतिशत	75.8 प्रतिशत
साक्षरता स्त्री	33.5 प्रतिशत	54.1 प्रतिशत
वार्षिक विकास दर	2.7 प्रतिशत	6.0 प्रतिशत
कृषि विकास दर	1.5 प्रतिशत	2.7 प्रतिशत
कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता	73 प्रतिशत	60.0 प्रतिशत
गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या	42.6 प्रतिशत	26.0 प्रतिशत
प्रतिव्यक्ति आय	3948 रुपये	13226 रुपये

स्रोत- विभिन्न सरकारी दस्तावेज

तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 27 जून, 2005को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफी धीमी है, किन्तु वर्तमान में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (C.S.O.) के आकलन में जहाँ घरेलू उत्पाद (GD 2003-04 में नकारात्मक (Negative) -5.15 प्रतिशत था वहीं 2004-05 से 2008-09 के बीच सकारात्मक (Positive) 11.03 प्रतिशत हो गया जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों से दूसरे नम्बर पर आ गया । गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.05 प्रतिशत रहा जबकि बिहार का 11.03 प्रतिशत रहा है । बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्री 'आश्चर्य का अर्थशास्त्र' (Miracle Economics) भी कहते हैं ।

बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय- आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है । बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफी जरूरी है । पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने कहा था कि **''बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है।''** बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा ।

बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं-

1. जनसंख्या पर नियंत्रण- राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए । इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए ।

2. कृषि का तेजी से विकास - बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है । अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लायी जा सके । इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है ।

3. बाढ़ पर नियंत्रण - बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है । फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है । जानमाल की भी काफी क्षति होती है। उत्तरी

बिहार की अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है।

दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है अत: सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुःखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है ।

4. आधारिक संरचना का विकास – बिहार में बिजली की काफी कमी है । अत: बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। सड़क-व्यवस्था में सुधार लाया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके।

बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय

1. जनसंख्या पर नियंत्रण
2. कृषि का तेजी से विकास
3. बाढ़ पर नियंत्रण
4. आधारिक संरचना का विकास
5. उद्योगों का विकास
6. गरीबी दूर करना
7. शांति व्यवस्था की स्थापना
8. स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन
9. केन्द्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण

5. उद्योगों का विकास– बिहार से झारखण्ड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था । मुख्यत: चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी जो अधिकतर बन्द पड़ी थी । लेकिन विगत् कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूँजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके ।

6. गरीबी दूर करना – बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है । गरीबी-रेखा के नीचे लगभग 42 प्रतिशत से भी अधिक लोग यहाँ जीवन-बसर कर रहे हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण (Training) दिया जाए।

7. शांति व्यवस्था की स्थापना– बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है।

8. स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन– बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल

तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है ।

9. केन्द्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण -बिहार के विकास के लिए केन्द्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण (Transfer of Resources) की जरूरत है। कुछ राज्यों को **विशेष राज्य का दर्जा** देकर उन्हें अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहायता दी जाती है । **विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर-पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रही है।**

चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता रहा है । **15 नवम्बर 2000 को बिहार से झारखण्ड के अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखण्ड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए ।** बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएँ यहाँ उपस्थित है । अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है । पिछले साल 2008 में कोशी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा । ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है । अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है । इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग जोरों से की जा रही है । इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफी किए जा रहे हैं । विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केन्द्र के द्वारा विकास के मद में अधिक सहायता तथा करों से रियायत मिलने लगेगी जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है । लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केन्द्र सरकार के समक्ष अनेक व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएँ आ रही हैं ।

देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका

ABDIEL SOLUTIONS ABSOL PATNA

बिहार देश का एक बड़ा राज्य है । भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्त्व रखता है । इसलिए कहा जाता है कि **''यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है।''**

चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की

बात हो, अब बिहार को नजर अंदाज नहीं कर सकते । एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **कुजनेठ (Kuznett)** ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि "गरीबी कैन्सर (Cancer) रोग की तरह है । जिस तरह शरीर के एक छोटे-से भाग में हुआ कैन्सर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है। ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है।"

उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते ।

बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि (Fertile Land) है । हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल-प्रवाह होता रहता है । यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ (River-inter-linking) कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलायी जा सकती है।

बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी (Technology) क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है बल्कि यहाँ के कम पढ़े-लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को फलीभूत बनाया है । देश के सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है ।

देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि-जन्य या कृषि-जनित उद्योगों (Agro-Based Industry) के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (C.S.O.) ने बिहार का

कृषि-जनित उद्योग

ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि-जनित उद्योग कहते हैं । उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि ।

वर्तमान विकास दर 11.03 प्रतिशत माना है जो देश में गुजरात (11.5%) के बाद दूसरा है ।

विगत् वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है । विकास की गति के कारण ही वर्त्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है । यह संतोष की बात है कि विगत् वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं । बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधा में कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को कारगर करे तो इक्कीसवीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा । अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्त्वपूर्ण है ।

ABDIEL SOLUTIONS ABSOL PATNA

मूलभूत आवश्यकताएँ एवं विकास का संबंध

देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढँकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है । हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से बुलन्द किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके । देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्त्ति करना रहता है । यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत् साठ से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं । देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है । अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है । इसके कारण **गरीबी-रेखा (poverty line)** के नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी

> **गरीबी-रेखा** (Poverty Line)- गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन (Border Line) किया गया है । गरीबी-रेखा कैलोरी मापदण्ड पर आधारित है । ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है । अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है । इस रेखा (Line) से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line) माना जाता है । इसे संक्षेप में BPL भी कहा जाता है ।

नरेगा (NREGA) ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम-से-कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनत्तम मजदूरी निर्धारित है।

नहीं आयी है।

समुचित न्यायपूर्ण **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (Public Distribution System) से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना (scheme) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act) के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में **"NREGA"** (नरेगा) कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है।

विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेद-भाव किए हुए सम्पूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक् विकास की अवधारणा महत्त्वपूर्ण हो गई है जिसे हम आर्थिक शब्दावली में **"Inclusive Growth"** कहते हैं। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है।

सारांश

- भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़े काफी गहरी है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को **"सोने की चिड़ियाँ"** कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का काफी शोषण हुआ।
- अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है।
- अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बाँटा गया है- (i) प्राथमिक क्षेत्र, (ii) द्वितीयक क्षेत्र तथा (iii) तृतीयक क्षेत्र।

- आज विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है - (i) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, (ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा (iii) मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।

- आर्थिक विकास (Economic Development) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

- भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है।

- आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है।

- आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रतिव्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report- HDR) विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक-स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर करती है।

- साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसके अनेक कारण हैं। हरेक साल बाढ़ तथा सूखा का प्रकोप इस राज्य को झेलना पड़ता है।

- आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था कि "बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है।"

- आजकल बिहार को "विशेष राज्य का दर्जा" देने की माँग केन्द्र सरकार से की जा रही है। यदि केन्द्र सरकार बिहारवासियों की यह माँग मान लेती है तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल सकता है। इस विशेष आर्थिक सहायता से बिहार अपनी स्थिति में सुधारकर अपना आर्थिक विकास कर सकता है।

- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के समक्ष अनेक व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएँ आ रही हैं।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें ।

1. निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।

   (क) सेवा क्षेत्र (ख) कृषि क्षेत्र
   (ग) औद्योगिक क्षेत्र (घ) इनमें से कोई नहीं

2. इनमें कौन-से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ?

   (क) अमेरिका (ख) चीन
   (ग) भारत (घ) इनमें से कोई नहीं

3. भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था ?

   (क) 15 मार्च 1950 (ख) 15 सितम्बर 1950
   (ग) 15 अक्टूबर 1951 (घ) इनमें से कोई नहीं

4. जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है।

   (क) अविकसित (ख) विकसित
   (ग) अर्द्ध-विकसित (घ) इनमें से कोई नहीं

5. इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है ?

   (क) पंजाब (ख) केरल (ग) बिहार (घ) दिल्ली

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ।

1. भारत अंग्रेजी शासन का एक .... था ।
2. अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का .... किया ।
3. अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की .... है ।
4. द्वितीयक क्षेत्र को .... क्षेत्र कहा जाता है ।
5. आर्थिक विकास आवश्यक रूप से .... की प्रक्रिया है ।
6. भारत में आर्थिक विकास का श्रेय .... को दिया जा सकता है ।

7. आर्थिक विकास की माप करने के लिए .... को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है ।
8. साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति .... है ।
9. बिहार में .... ही जीवन का आधार है ।
10. बिहार के विकास में .... एक बहुत बड़ा बाधक है ।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short- Answer Questions)

1. अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ?
2. मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ?
3. सतत् विकास क्या है ?
4. आर्थिक नियोजन क्या है ?
5. मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report) क्या है ?
6. आधारिक संरचना (Infrastructure) पर प्रकाश डालें ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. अर्थव्यवस्था की संरचना (Structure of Economy) से क्या समझते हैं ? इन्हें कितने भागों में बाँटा गया है ?
2. आर्थिक विकास क्या है ? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें।
3. आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें ।
4. बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं ? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावें ।

परियोजना कार्य (Project Work)

1. अपने गाँव या शहर के आर्थिक विकास के संदर्भ में एक परियोजना प्रस्तुत करें।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर

I. 1. (ख) 2. (ग) 3. (क) 4. (ख) 5. (ग)

II. 1. उपनिवेश 2. शोषण 3. प्रणाली 4. औद्योगिक 5. परिवर्तन 6. नियोजन 7. प्रतिव्यक्ति आय 8. दयनीय 9. कृषि 10. बाढ़

*